

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कियी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के माह 12/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ए०के०श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2017 से 01.09.2017 तक श्री प्रेमचन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस०के० सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2014 से 17.12.2017 तक श्री पी०सी० श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- चमोली

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् है:-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य +)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	-	-	2336.4 7	2336.4 7	-	-
2015-16	-	-	-	-	2554.4 9	2554.4 9	-	-
2016-17	-	-	-	-	3199.4 6	3199.4 6	-	-
2017-18	-	-	-	-	3924.0 2	1213.5 3	-	2710.4 9

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत-राज्य एवं केन्द्र ) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है: पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक( , (आर०आई०, ना०पु० एवं सा०पु०), उप-निरीक्षक (ना०पु०, सा०पु०, एम०), सहा० उप-निरीक्षक (ना०पु०, सा०पु०, एम०), हे०का० , कान्स० एवं चतुर्थ श्रेणी।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, चमोली की लेखा परीक्षा में पाये गये

निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-II 'अ'

**प्रस्तर:1-** मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 24.66 लाख की धनराशि कम वसूल किये जाने के कारण राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अगस्त 2016 के बिन्दु 2 के धारा 179 (i) अनुसार विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करने पर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधो पर रू 500 वाहन स्वामी से प्रशमन कर सकेगें का प्रावधान है। लेकिन ऐसा न कर निम्न थाना के प्रभारी एवं उप निरीक्षकों द्वारा रू 500 के स्थान पर 100 प्रति वाहन वसूल लिया गया है। जिसके कारण रू 24.66 लाख की कम धनराशि वसूल किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	थाना का नाम	अवधि	धारा सं०	प्रकरणों की संख्या	चालान किये गये वाहनो से वसूल की गई धनराशि	एम वी एक्ट के अनुसार वसूल किया जाना था	कम वसूल की गई धनराशि
01.	गोपेश्वर	11/8/16 से 07/17	179(i)	300	100	500	120000
02.	पोखरी	11/8/16 से 07/17	179(i)	175	100	500	70000

03.	थराली	11/8/16 से 07/17	179(i)	858	100	500	343200
04.	चमोली	11/8/16 से 07/17	179(i)	1845	100	500	738000
05.	कर्णप्रयाग	11/8/16 से 07/17	179(i)	2433	100	500	973200
06.	जोशीमठ	11/8/16 से 07/17	179(i)	94	100	500	36600
07.	बद्रीनाथ	11/8/16 से 07/17	179(i)	327	100	500	138800
08.	गोविन्दघाट	11/8/16 से 07/17	179(i)	76	100	500	30400
09.	यातायात लाइन	11/8/16 से 07/17	179(i)	40	100	500	16000
योग:							2466200

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि वर्तमान में समस्त थानों एवं क्षेत्राधिकारियों शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु अलग निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण शासनादेश में दिये गये धारा 179(i)के अनुसार चालान किये गये वाहनों से कम धनराशि की वसूली किया जा रहा था।

अतः मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 27.46 लाख की धनराशि कम वसूल किया जाने से राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**कार्यालय: पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली**

**चालान किये गये वाहन से रू 400 प्रति वाहन कम वसूली की गई धनराशि का विवरण**

क्र०सं०	थाना का नाम	अवधि	धारा सं०	चालान किये गये वाहन की संख्या	वसूल की गई धनराशि	एम वी एक्ट अनुसार वसूल किया जाना था	रू 400 प्रति वाहन कम वसूल की गई धनराशि
01	गोपेश्वर	11/8/16से 07/17	179(i)	300	100	500	120000
02	पोखरी	11/8/16से 7/17	179(i)	175	100	500	70000
03	थराली	11/8/16से 7/17	179(i)	858	100	500	343200
04	चमोली	11/8/16से 7/17	179(i)	1845	100	500	738000
05	कर्णप्रयाग	11/8/16से 7/17	179(i)	2433	100	500	973200
06	जोशीमठ	11/8/16से 7/17	179(i)	94	100	500	36600
07	बद्रीनाथ	11/8/16से 7/17	179(i)	327	100	500	138800
08	गोविन्दघाट	11/8/16से 7/17	179(i)	76	100	500	30400
09	यातायात लाइन	11/8/16से 7/17	179(i)	40	100	500	16000
योग:							2466000

### भाग-दो 'ब'

**प्रस्तर:1-** थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु अनुउपर्युक्त भूमि के चयन के कारण रू 21.25 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किया जाना एवं रू 28.22 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत सात वर्षों से अवरूद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2010 पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना 2009-10 के अन्तर्गत जनपद चमोली में थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रू 70.27 लाख की धनराशि व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई थी। इसी क्रम में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अप्रैल 2010 में स्वीकृत धनराशि में से 10 प्रतिशत रोकते हुए अवशेष धनराशि रू 6324300/ बैंक ड्राफ्ट संख्या 798537 दिनांक 31.03.2010 को संलग्न कर अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी चमोली को प्रेषित कर दिया गया। साथ ही साथ कार्यदायी संस्था से एम ओ यू कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा जून 2011 तक एम ओ यू नहीं किया गया था।

कार्यालय के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु उक्त भूमि के अतिरिक्त पोखरी में पुलिस विभाग के नाम अन्य कोई भूमि दर्ज नहीं है। उक्त भूमि पर ही थाना भवन का निर्माण किया जाना है। अपके भू-वैज्ञानिक द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण दिनांक 08.07.2011 को किया गया था। जिसमें उक्त भूमि को अनुपयुक्त पाया गया। जबकि भूमि को वर्ष 2008 एवं वर्ष 2010 में भूसर्वेक्षण किया गया है। जिसमें भूमि को भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा जुलाई 2011 में पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून को यह अवगत कराया था कि थाने के प्रशासनिक भवन को निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को विगत वर्ष में स्वीकृत हुआ था। लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया था कि चयनित स्थल निर्माण हेतु अनुपयुक्त है, भविष्य में स्थल के पास भूस्खलन एवं भूमि -धसाव होने की सम्भावना है। जोकि भवन के लिये सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है व भवन निर्माण हेतु अन्य स्थल को चयनित करने हेतु अवगत कराया है।

थाना पोखरी के पत्र दिनांक 20.01.2014 द्वारा यह अवगत कराया था कि अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी के तारतम्य में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2013 में पुलिस थाना कार्यालय भवन हेतु स्थल का विकास कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया था। किन्तु वर्ष 2013 में भारी वर्षा के कारण कार्य स्थल पर अत्यधिक मात्रा में मलवा आ गया था जिस कारण ठेकेदार द्वारा जिन दीवारों का निर्माण कार्य किया गया था, पूर्ण रूप क्षतिग्रस्त हो गयी थी। कार्य स्थल पर अत्यधिक मलवा आने एवं सुरक्षा दीवार के क्षतिग्रस्त होने के कारण ठेकेदार ने भवन निर्माण में असमर्थता व्यक्त की है। वर्तमान में कार्य स्थल से मलवा हटाये जाने एवं दीवारों के निर्माण कार्य करने के पश्चात ही मुख्य भवन का कार्य करना सम्भव हो पायेगा। मलवा का निस्तारण एवं सुरक्षा दीवार की निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू 35.34 लाख का प्राङ्कलन प्रेषित किया गया था। परन्तु अभी तक स्वीकृत अप्राप्त है। जबकि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 20.03.2015 थी। कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 19.08.2016 थी।

आगे जांच में यह भी पाया गया है कि सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी केवल समतलीयकरण कार्य कार्य पूर्ण हो पाया है, तथा बुनियाद का कार्य चल रहा है। वर्तमान तक केवल रू 21.25 लाख धनराशि ही व्यय किया गया था। अवशेष धनराशि रू 28.22 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि समस्त बिन्दुओं के उत्तर कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है

क्योंकि वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा निर्माण के लिए अनुपर्युक्त पाये जाने के बाद भी उसी स्थान पर पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु अनुपर्युक्त भूमि के चयन के कारण रु 21.25 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किया जाना एवं रु 28.22 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत सात वर्षों से अवरूद्ध रखा जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

#### भाग-दो 'ब'

**प्रस्तर-3-** रु 25.06 लाख की यातायात व्यवस्था एवं चारधाम यात्रा हेतु सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के प्रस्तर 12 (1) के अनुसार रु 3 लाख से रु 60 लाख तक की सामग्री का क्रय सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाकर क्रय किये जाने का प्रावधान है।

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र डीजी-तीन-गोष्ठी/2017 दिनांक 18 जनवरी 2017 को पुलिस यातायात के सुदृढीकरण हेतु रु 6 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष रु 6 लाख की धनराशि व्यय कर दी गई है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 527xx-8/16-12(11) 2016 दिनांक 25 मई 2016 द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात पुलिस कर्मियों की भोजन व्यवस्था, यात्रा व्यय एवं अन्य तात्कालिन कार्यों की व्यवस्था पर व्यय हेतु जनपद-चमोली के लिए रु 25 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। अवमुक्त धनराशि का व्यय कर दिया गया था।

कार्यालय के यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि यातायात के सुदृढीकरण हेतु सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर रु 6.00 लाख एवं चारधाम यात्रा हेतु अवमुक्त धनराशि रु 25.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु 19.06 लाख की धनराशि व्यय कर दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि 25 लाख का व्यय एक दुकान एवं फर्म से नहीं किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा क्रय प्रणाली में निविदा प्रक्रिया का पालन न कर कोटेशन के आधार पर टुकड़ें-2 में क्रय किया गया है। जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन किया गया है।

अतः रू 25.06 लाख की यातायात व्यवस्था एवं चारधाम यात्रा हेतु सामग्री का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

#### भाग-दो 'ब'

**प्रस्तर-4-** मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व रू 3.46 लाख की धनराशि को विलम्ब से राजकोष में जमा कराया जाना।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या- डीजी-यातायात0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को 'मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर संयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं संयोजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव' के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि-मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उ0एस0नगर में संयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को प्रति-दिन एवं शेष जनपदों में उक्त धनराशि सप्ताह में एक बार (मंगलवार) को राजकोष में जमा कराया जायें। प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/तिमाही में ऑडिट कराया जाये।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली द्वारा बैंक के माध्यम से राजकोष में जमा कराये गये चालान फर्मों एवं उनके साथ संलग्न जनपद के विभिन्न थानों द्वारा प्रत्येक दिन किये गये चालानों का तिथि-मय विवरणों की जांच में पाया गया कि जनपद के विभिन्न थानों एवं कोतवालियों से माह मई, 2017 में प्राप्त रू 2.20 लाख(संलग्न परिशिष्ट 'अ') की नगद धनराशि को 14-दिनों से 68- दिनों तक तथा माह मार्च, 2017 में प्राप्त रू 1.26 लाख (संलग्न परिशिष्ट 'ब') की नगद धनराशि को 20-दिनों से 45-दिनों तक अर्थात् उक्त दोनों माहों की कुल प्राप्ति रू 3.46 लाख की नगद धनराशि को 14-दिनों से 68-दिनों के विलम्ब/देरी से कार्यालय में जमा करायी जा रही थी, जबकि मुख्यालय के निर्देशानुसार संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व की धनराशि को साप्ताहिक जनपद के प्रश्नगत थानों से प्राप्त करके उक्त चालानों के माध्यम से राजकोष में जमा करायी जानी चाहिए थी। जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय द्वारा न केवल मुख्यालय के निर्देशों का बल्कि सी0जी0ए0 (प्राप्तियां एवं भुगतान)नियमावली 1983 के नियम-18 का भी उल्लंघन किया गया था।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि मुख्यालय के निर्देश जनपद में प्राप्त न होने के कारण अनुपालन नहीं किया गया था भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## परिशिष्ट-'अ'

माह:- मई, 2017						
क्र० स०	थाने का नाम	अवधि	संयोजन शुल्क जमा करने की तिथि	दिवसों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	गोपेश्वर	13.03.2017 से 20.05.2017	29.05.2017	68	76	14000
2	कोतवाली श्री बद्रीनाथ	15.05.2017 से 21.05.2017	29.05.2017	14	24	6100
3	कोतवाली चमोली	14.05.2017 से 20.05.2017	29.05.2017	14	128	22200
4	गोविन्द घाट	14.05.2017 से 18.05.2017	29.05.2017	14	25	5200
5	थराली	09.05.2017 से 19.05.2017	29.05.2017	19	35	3800
6	कोतवाली कर्णप्रयाग	15.05.2017 से 21.05.2017	29.05.2017	14	81	9200
7	जोशीमठ	15.05.2017 से 21.05.2017	29.05.2017	14	28	2800
8	पुलिस लाइन गोपेश्वर	16.05.2017 से 16.05.2017	29.05.2017	13	13	2200
9	कोतवाली चमोली	09.04.2017 से 22.04.2017	11.05.2017	31	92	9300
10	थराली	12.04.2017 से 22.04.2017	11.05.2017	28	16	2200
11	कोतवाली कर्णप्रयाग	08.04.2017 से 15.04.2017	11.05.2017	32	79	8100
12	गोपेश्वर	10.04.2017 से 16.04.2017	11.05.2017	30	61	6400
13	थराली	06.04.2017 से 15.04.2017	11.05.2017	34	44	7500
14	जोशीमठ	18.04.2017 से 22.04.2017	11.05.2017	22	11	1200
15	कोतवाली जोशीमठ	10.04.2017 से 15.04.2017	11.05.2017	30	25	2500
16	गोविन्दघाट	18.04.2017 से 20.04.2017	11.05.2017	22	13	2300
17	थराली	18.04.2017 से 27.04.2017	11.05.2017	22	15	1700
18	गोविन्दघाट	24.04.2017 से 28.04.2017	11.05.2017	16	14	2400
19	कोतवाली चमोली	23.04.2017 से 29.04.2017	11.05.2017	17	107	14500
20	पोखरी	14.04.2017 से 28.04.2017	11.05.2017	26	47	5600
21	जोशीमठ	25.04.2017 से 29.04.2017	11.05.2017	15	10	1000
22	गोपेश्वर	17.04.2017 से 23.04.2017	11.05.2017	23	86	12350
23	कोतवाली कर्णप्रयाग	14.04.2017 से 23.04.2017	11.05.2017	26	200	23200
24	गोपेश्वर	24.04.2017 से 30.04.2017	11.05.2017	16	77	11000
25	थराली	07.05.2017 से 10.05.2017	22.05.2017	15	28	2900
26	कोतवाली कर्णप्रयाग	27.04.2017 से 07.05.2017	22.05.2017	25	70	7700
27	गैरसैण	11.04.2017 से 11.05.2017	22.05.2017	30	45	4500

28	थराली	24.04.2017 से 30.04.2017	22.05.2017	28	30	3300
29	पोखरी	01.05.2017 से 07.05.2017	22.05.2017	21	16	1900
30	कोतवाली चमोली	07.05.2017 से 12.05.2017	22.05.2017	15	103	15000
31	जोशीमठ	02.05.2017 से 07.05.2017	22.05.2017	20	28	3300
32	गोपेश्वर	01.05.2017 से 07.05.2017	22.05.2017	21	33	4950
		<b>योग</b>				<b>220300</b>

## परिशिष्ट- 'ब'

माह:- मार्च, 2017						
क्र० स०	थाने का नाम	अवधि	संयोजन शुल्क जमा करने की तिथि	दिवसों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	कोतवाली चमोली	19.02.2017 से 04.03.2017	23.03.2017	31	257	25900
2	गोविन्दघाट	22.02.2017 से 24.02.2017	23.03.2017	28	9	1200
3	कोतवाली जोशीमठ	03.03.2017 से 05.03.2017	23.03.2017	20	16	1600
4	गोपेश्वर	20.02.2017 से 26.02.2017	23.03.2017	30	75	8100
5	थराली	06.02.2017 से 26.02.2017	23.03.2017	44	61	8800
6	कोतवाली जोशीमठ	21.02.2017 से 26.02.2017	23.03.2017	29	38	4900
7	कोतवाली कर्णप्रयाग	18.02.2017 से 02.03.2017	23.03.2017	32	268	28850
8	गोपेश्वर	27.02.2017 से 05.03.2017	23.03.2017	23	92	11150
9	गैरसैण	22.01.2017 से 26.01.2017	23.03.2017	28	29	4500
10	कोतवाली चमोली	19.02.2017 से 26.02.2017	23.03.2017	31	18	4500
11	थराली	26.02.2017 से 03.03.2017	23.03.2017	24	33	5100
12	कोतवाली चमोली	05.02.2017 से 18.02.2017	23.03.2017	45	191	21100
		<b>योग</b>				<b>125700</b>



**STAN****प्रस्तर:1- विभाग को संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व के प्रति उदासीनता का प्रकरण।**

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून, दिनांक: जून 24, 2016 के पत्र संख्या- डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को 'मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर संयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं संयोजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव' के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि- प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/ में कराये। तथा अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई त्रैमासिक सम्प्रेक्षा का विस्तृत विवरण सम्बंधित जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को दी जाये। समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जमा की गयी संयोजन शुल्क धनराशि की छः माह की सूचना पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करे।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण एवं वापसी पंजिका की जांच में पाया गया कि माह मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक जनपद के विभिन्न थानों एवं कोतवालियों को वितरित की गयी संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं में से 16-संयोजन शुल्क पुस्तिका एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जनपद के संदर्भित थानों द्वारा उक्त पुस्तिकाए(तृतीय प्रति) जनपद कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। विवरण संलग्नक (परिशिष्ट- 'अ')। इसी प्रकार उक्त पंजिकाओं के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंजिकाओं में अगस्त, 2012 से जून, 2016 तक कार्यालय द्वारा विभिन्न थानों को वितरित की गयी संयोजन पुस्तिकाओं का संदर्भित पंजिका में स्तम्भबद्ध ढग से प्रविष्टियां दर्ज न करने के कारण यह ज्ञात नहीं हो पाया कि कुल जारी पुस्तिकाओं में कौन-सी पुस्तिका वापस कार्यालय को प्राप्त हुयी थी तथा कौन-सी पुस्तिका वापसी हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर लम्बित थी साथ ही संदर्भित पंजिका के किसी भी पृष्ठ पर कार्यालय द्वारा जनपद के थानों से पुरानी पुस्तिकाओं की वापसी का विवरण तथा रख-रखाव से सम्बंधित लेखाबन्दी या मासिक सार नहीं बनाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप जनपद के संदर्भित थानों में पुरानी संयोजन शुल्क पुस्तिकाए विगत एक वर्ष से अधिक समय से वापसी हेतु लम्बित पड़ी थी। जबकि कई थानों द्वारा कार्यालय से पुरानी संयोजन शुल्क पुस्तिकाए वापसी किये बिना नई पुस्तिकाए निरन्तर प्राप्त कर रहे थे जबकि संयोजन शुल्क पुस्तिकाए विभाग में राजस्व का एक प्रारम्भिक/मुख्य अभिलेख है।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा। विभाग के उत्तर से 'राजस्व प्राप्ति' के प्रति विभागीय लापरवाई स्पष्ट होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

परिशिष्ट- 'अ'

वापसी न हुई संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं का विवरण: माह मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक				
क्र० स०	संयोजन शुल्क वितरण पंजिका का पृष्ठ संख्या	संयोजन शुल्क पंजिका संख्या।	थानों का नाम(जिसको पुस्तिका जारी की गयी है)	तिथि (जिस तिथि को प्राप्तकर्ता ने पुस्तिका प्राप्त की है)

1	06	501 से 550	थाना-चमोली	31.03.2016
2	06	551 से 600	थराली	01.04.2016
3	06+	601 से 650	पी0एस0सी0एम0आई0	04.04.2016
4	06	651 से 700	पी0एस0जी0एस0एन0	12.04.2016
5	06	701 से 750	पी0एस0पी0के0आई0	21.04.2016
6	07	751 से 800	पी0एस0सी0एम0आई0	27.04.2016
7	07	801 से 850	मेहलचौरी	29.04.2016
8	पंजिका का क्र0स0-402	512901 से 512950	थराली	15.07.2016
9	पंजिका का क्र0स0-404	798101 से 798150	दिगम्बर सिंह उनियाल	15.07.2016
10	पंजिका का क्र0स0-405	512501 से 512550	गौचर	15.07.2016
11	पंजिका का क्र0स0-408	512601 से 512700	कोतवाली कर्णप्रयाग	19.07.2016
12	पंजिका का क्र0स0-410	221551 से 221600	कोतवाली कर्णप्रयाग	23.07.2016
13	पंजिका का क्र0स0-411	798401 से 798450	कोतवाली कर्णप्रयाग	26.07.2016
14	पंजिका का क्र0स0-413	507501 से 507550	एस0ओ0 कर्णप्रयाग	29.07.2016
15	पंजिका का क्र0स0-414	507551 से 597600	चौकी बाजार	29.07.2016
16	पंजिका का क्र0स0-415	797951 से 798000	गौचर	29.07.2016

### STAN

#### प्रस्तर:2-- स्वीकृत नियतन से अधिक अधिकारी/कर्मचारियों का कार्यरत रहने का प्रकरण।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12- अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत नियतन के सापेक्ष अधिक कार्यरत/उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	अधिकता
1	कान्स0 (एम0) प्रधान लिपिक/आंकिक कार्यालय	01	03	02
2	अस्थायी चालक	00	02	02
3	बम डिस्पोजल कान्स0	00	05	05
4	श्वान दल कान्स0	00	02	02
5	श्वान दल चतुर्थ श्रेणी	00	01	01
	<b>योग</b>	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त आपत्ति के सम्बंध में इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि

उक्त नियुक्ति पुलिस मुख्यालय स्तर से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बट्टीनाथ/हेमकुण्ड+ साहिब एवं जनपद में आने वाले विभिन्न महानुभावों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किये गये है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि इकाई को उक्त उपलब्ध पदों पर अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों की

आवश्यकता थी तो स्वीकृत नियतन को विधिवत मुख्यालय/ शासन से संशोधित करवाया जाना चाहिए था जोकि की इकाई द्वारा न तो मुख्यालय को अवगत करवाया है न ही संशोधन हेतु कोई भी उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### **STAN**

#### **प्रस्तर:3- स्वीकृत नियतन से अधिक वाहन रखे जाने का प्रकरण।**

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के अधीन परिवहन- शाखा के वाहनों का स्वीकृत नियतन से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वीकृत नियतन 31-वाहनों के सापेक्ष कार्यालय में निम्नलिखित कुल 48- वाहन उपलब्ध है अर्थात् स्वीकृत नियतन से कुल 17-वाहन अधिक उपलब्ध है। विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	वाहन का नाम प्रकार	स्वीकृत नियतन	उपलब्ध	अधिक
1	हल्का वाहन कार सहित	01	02	01
2	इन्टर सैफ्टर	00	01	01
3	एम्बेसडर कार	00	01	01
4	भारी वाहन 32 सीटर बस	00	01	01
5	भारी वाहन ट्रक	01	02	01
6	प्रीजन वाहन बड़ा एवं छोटा	02	04	02
7	केन बड़ा एवं छोटा	01	02	01
8	मोटर साईकिल	00	08	08
9	एम्बुलेंस	01	02	01
	<b>योग</b>	<b>06</b>	<b>23</b>	<b>17</b>

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में कहा है कि कुछ वाहन जैसे: केन एवं एम्बुलेंस भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये थे तथा स्वीकृत नियतन के संशोधन हेतु मुख्यालय से पत्राचार किया जायेगा।

अतः स्वीकृत वाहन से अधिक वाहन रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
43/2011-12	-	प्रस्तर:2- पुनरीक्षित आगणन रू 94.45 लाख स्वीकृत होने के डेढ़ वर्ष बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण। प्रस्तर:4- इन्डो नेपाल बार्डर डिस्ट्रीक हेतु क्रय वाहन के अनुपयोग रहने से रू 11.64 लाख को निष्फल व्यय। प्रस्तर:6- धनराशि रू 90.81 लाख का अवरोधन।	-
27/2014-15	-	प्रस्तर:1- 46.07 लाख की धनराशि विगत 7 वर्षों से निर्माण इकाई के पास अवरूद्ध रखा जाना।	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
43/2011-12		प्रस्तुत	निस्तारित करने हेतु संस्तुति की गई है।	
27/2014-15		अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:-शून्य

## भाग-V

### आभार

- 1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **पुलिस अधीक्षक, जनपद- चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।  
तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-शून्य
- 2- सतत् अनियमितताये:- शून्य
- 3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1	सुश्री पी. रेणुका देवी	एस०पी० (आई०पी०एस०)	21.04.2012	15.06.2013
2	श्री अजय जोशी	एस०पी० (आई०पी०एस०)	15.06.2013	29.01.2014
3	श्री सुनील कुमार मीणा	एस०पी० (आई०पी०एस०)	30.01.2014	09.02.2016
4	श्रीमती प्रीती प्रियदर्शनी	एस०पी० (आई०पी०एस०)	10.03.2016	07.04.2017
5.	सुश्री तृप्ति भट्ट	एस०पी० (आई०पी०एस०)	08.04.2017	अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।